पहलुओं--पर्यावरणीय और जनसांख्यिकीय--पर विचार किया जाना है । अतः यह बताना सम्भव नहीं है कि अन्तिम निर्णय कब तक लिया जाएगा ।

Deaths on Rail tracks around Delhi

390. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Wil the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) what is the comparative percentage of rise in the deaths on rail tracks around Delhi during the last three years till date;

(b) what are the main causes therefor stating the areas which are most vulnerable to such incidents;

(c) whether in view of the rising incidents of deaths on rail tracks, Government have made any review of the existing strengh of Railway Police in Delhi to ascertain its adequacy or otherwise to deal with the situation; and

(d) if so, by what percentage the strength of the Railway Police in Delhi has been raised/proposed to be raised to deal with the problem besides other steps contemplated by Government in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) The requisite figures are indicated below:

Year	Total number of deaths	Percentage increase over previous year
1984	351	—
1985	438	19% over 1984
1986	465	5.08%over 1985
1987 (upto 31-3-87	115	

(b) A large number of new setlement colonies have come up along the railway tracks in Delhi. Many fast moving trains have now been introduced. Such accidents occur due to careless attempts to cross the railway tracks. Areas like Shahdara, Azadpur, Rampura, Naraina and Delhi Cantt are more prone to such accidents.

(c) and (d) Raising the strength of the Railway Police in Delhi will not be of much help in this regard.

स्वदेशी काटन मिल्स, इलाहाबाद के कर्मचारियों द्वारा अनशन तथा भूख हड़ताल

391. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :** क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वदेशी काटन मिल्स, नैनी, इलाहाबाद के कर्मचारियों ने 20 मार्च, 1987 से मिल के गेट पर क्रमिक अनशनों, भूख हड़तालों तथा प्रदर्शनों आदि का सिलसिला चला रखा है ; और

(ख) यदि हां, तो कर्मचारियों की मांगें क्या हैं और इन्हें पूरा न किए जाने के क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : जी, हां ।

(ख) कामगारों की मांगों में शामिल हैं :--

(1) अन्तरिम वृद्धि के बतौर प्रति माह 60 रु० का भुगतान ।

(2) 1 65 रु० की दर पर बी डी ए पाइंट का परिकलन ।

(3) कुछ अतिरिक्त भत्तों आदि का भुगतान ।

उप श्रमिक आयुक्त द्वारा वार्तालाप के बावजूद कामगारों द्वारा उठाई गई मांगों का निपटान नहीं किया जा सका क्योंकि वे इस संबंध में राज्य सरकार के आदेशों/निर्णयों से भिन्न हैं क्योंकि क्षेत्र-सह-उद्योग आधार पर जुड़े होते हैं ।